उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 5 अंक 5 1-15 मार्च 2022 ₹ 20/-

उत्तर प्रदेश में मुस्लिम विधायकों की संख्या में वृद्धि

- भागलपुर बम धमाके में 14 मरे
- पाकिस्तान में शियाओं पर कहर
- सऊदी अरब में 81 लोगों को मृत्युदंड
- दिल्ली के इमामों को 11 महीने के वेतन का भुगतान

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

* अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

उत्तर प्रदेश में मुस्लिम विधायकों की संख्या में वृद्धि 04
विधान सभा चुनाव उर्दू प्रेस की नजर में 05
भागलपुर बम धमाके में 14 मरे 09
बिहार विधान सभा में हंगामा 10
निजामुद्दीन स्थित तब्लीगी मरकज अभी नहीं खुलेगा 11

विश्व

पाकिस्तान में शियाओं पर कहर 12
चीन के रक्षा बजट में वृद्धि 13
बांग्लादेश के बिहारी मुसलमानों के कल्याण के लिए योजना 14
सिराजुद्दीन हक्कानी का अज्ञातवास समाप्त 15
पश्चिमी देशों में अस्त्र-शस्त्र खरीदने की होड़ 15

पश्चिम एशिया

सऊदी अरब में 81 लोगों को मृत्युदंड 16
सऊदी अरब में कोरोना से संबंधित प्रतिबंध समाप्त 17
इजरायली संसद में फिलिस्तीनियों को नागरिकता न देने का कानून पारित 18
तुर्की इजरायल के साथ रक्षा सहयोग के लिए तैयार 19
ईरान ने अपना दूसरा सैन्य उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा 20

अन्य

दिल्ली के इमामों को 11 महीने के वेतन का भुगतान 21
मुगल बादशाह शाहजहां के उर्स में सतरंगी चादर पेश 21
करोड़ों रुपये की संपत्ति वक्फ बोर्ड को वापस करने का निर्देश 22
नेपाल की राष्ट्रीय सभा में मुस्लिम सदस्य का मनोनयन 22
श्रीनगर की जामा मस्जिद में 30 सप्ताह के बाद जुमे की नमाज 22

सारांश

उत्तर प्रदेश विधान सभा के इस बार के चुनाव में पिछली बार की तुलना में 10 मुस्लिम विधायक ज्यादा चुनकर आए हैं। 2017 के विधान सभा चुनाव में 24 मुस्लिम विधायक निर्वाचित हुए थे। जबकि इस बार के विधान सभा चुनाव में 34 मुस्लिम विधायक निर्वाचित हुए हैं। प्रदेश के मुसलमानों ने 1984 के बाद पहली बार एकजुट होकर योगी सरकार को हराने के लिए अपने मतों का इस्तेमाल किया। हालांकि वे इसमें सफल नहीं हुए। अजीब बात यह है कि उन्होंने ऐसी किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं किया, जिनके बार में वे समझते थे कि ये पार्टियां भाजपा के पुनः सत्ता में आने में बाधक नहीं बनेंगी। यही कारण है कि उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वेल्फेयर पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस को ठुकरा दिया। इसके साथ ही हमें इस बात को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में अतिवादी मुस्लिम संगठन बड़ी तेजी से अपने पैर पसार रहे हैं। मणिपुर के इतिहास में 2022 के विधान सभा चुनाव में पहली बार तीन मुस्लिम विधायक निर्वाचित हुए हैं।

यदि हाल के राज्य विधान सभा चुनावों के चुनावो अभियान का विश्लेषण किया जाए तो उर्दू प्रेस और विशेष रूप से मुस्लिम प्रेस के लिए य चुनाव पूरी तरह से अप्रत्याशित हैं। शुरू से ही उर्दू प्रेस भाजपा और संघ परिवार के खिलाफ धुआंधार प्रचार अभियान चला रहा था। इसके बावजूद इन चुनाव परिणामों से उनके बनाए गए काल्पनिक दुर्ग ध्वस्त हो गए। अब मुस्लिम संस्थाओं और विशेष रूप से जमात-ए-इस्लामी द्वारा इस बात का प्रचार किया जा रहा है कि सभी सेक्युलर दलों ने आज तक मुस्लिम मतदाताओं को छलने का काम किया है। इसलिए मुसलमानों को अपना सशक्त नेतृत्व विकसित करना चाहिए।

इस्लामिक एकता और भाईचारे का बहुप्रचारित गुब्बारा अब फूट रहा है। हाल ही में सऊदी अरब ने एक दिन के अंदर 81 असंतुष्ट विद्रोहियों को मौत की सजा दी है। हालांकि सरकारी मीडिया का यह कहना है कि जिन लोगों की गर्दनें जल्लाद ने काटी हैं वे तस्कर और मासूम लोगों के हत्यारे थे, मगर ईरान ने इस दावे का भंडाफोड़ कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने सऊदी अरब के साथ वार्ता के दरवाजे बंद कर दिए हैं और इस बात की घोषणा की है कि सऊदी अरब की सुन्नी सरकार ने जिन लोगों को मौत के घाट उतारा है उनमें से अधिकांश शिया हैं और उनका एक मात्र गुनाह यह था कि वे सऊदी अरब के शासक परिवार के तानाशाही रवैये के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे थे।

शिया-सुन्नी विवाद सऊदी अरब तक ही सीमित नहीं है। उसने अब पाकिस्तान में भी पूरी तरह से अपने पैर फैला लिए हैं। हाल ही में पेशावर को शिया मस्जिद में जो आत्मघाती हमला हुआ उसके पीछे सुन्नी संगठन इस्लामिक स्टेट का हाथ पाया गया है। इस हमले में 75 से अधिक लोगों के मारे जाने की सूचना है। इस हमले के खिलाफ पूरे पाकिस्तान में शियाओं ने विरोध-प्रदर्शन किए हैं और इस बात पर रोष प्रकट किया है कि पाकिस्तान सरकार उन्हें सुरक्षा प्रदान करने में विफल रही है। इस समय पाकिस्तान में चार सुन्नी संगठन ऐसे हैं जो खुलेआम शियाओं को हिंसा का निशाना बना रहे हैं।

चीन ने अपने रक्षा बजट में भारी वृद्धि की है। इसके साथ ही चीनी सरकार ने अपने सैनिकों को अत्याधुनिक अस्त्र-शस्त्रों से लैश करने की योजना को भी गंभीरता से कार्यान्वित करना शुरू किया है। मीडिया की सूचनाओं के अनुसार इस समय सैनिक बजट की दृष्टि से चीन विश्व में दूसरे नंबर पर है और चीन की सेना विश्व की सबसे बड़ी सेना है। अजीब बात है कि इसके बावजूद इस बार भारत सरकार ने अपने रक्षा बजट में भारी कटौती की है।

राष्ट्रीय

उत्तर प्रदेश में मुस्लिम विधायकों की संख्या में वृद्धि

उत्तर प्रदेश विधान सभा 2022 के चुनाव में मुसलमानों ने एकजुट होकर वोट देने की जो रणनीति बनाई थी वह काफी सफल रही है। इस बार 34 मुस्लिम विधायक चुने गए हैं। जबकि 2017 में मुस्लिम विधायकों की संख्या 24 थी। इस बार 31 मुस्लिम विधायक समाजवादी पार्टी के टिकट पर निर्वाचित हुए हैं। जबकि राष्ट्रीय लोक दल के टिकट पर 2 और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के टिकट पर एक मुस्लिम उम्मीदवार मऊ से निर्वाचित हुआ है। नवनिर्वाचित मुस्लिम विधायकों के चुनावी परिणामों का विश्लेषण करने से एक बात साफ होती है कि मुसलमानों ने एकजुट होकर समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक दल को अपने वोट दिए हैं। शायद उनकी रणनीति उन दलों को एकजुट होकर समर्थन देने की थी जो भाजपा को सत्ता में आने से रोक सकें।

भाजपा ने किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को हालांकि मैदान में नहीं उतारा था, मगर उसके सहयोगी दल अपना दल की ओर से एक मुस्लिम उम्मीदवार हैदर अली खान को रामपुर जिले के स्आर क्षेत्र से आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के मुकाबले में मैदान में उतारा गया था, मगर व बुरी तरह से चुनाव हार गए। सबसे ज्यादा 88 मुस्लिम उम्मीदवार बहुजन समाज पार्टी ने मैदान में उतारे थे मगर उनमें से कोई चुनाव नहीं जीत पाया। समाजवादी पार्टी ने 64 मुसलमानों को मैदान में उतारा था, जिसमें से 31 चुने गए। कांग्रेस ने 75 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। जबकि इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 60 से अधिक मुस्लिम उम्मीदवारां को मैदान में उतारा, मगर उनमें से कोई सफल नहीं हुआ।

इंकलाब (11 मार्च) और **रोजनामा सहारा** (11 मार्च) के अनुसार चुने गए मुस्लिम उम्मीदवारों के नाम और उनके विधान सभा क्षेत्र निम्नलिखित हैं।

क्र.सं.	विधानसभा क्षेत्र	उम्मीदवार
1.	बेहट	उमर अली खान
2.	कैराना	नाहिद हसन
3.	थाना भवन	अशरफ अली खान
4.	नजीबाबाद	तसलीम अहमद
5.	कांठ	कमाल अख्तर
6.	ठाकुरद्वारा	नवाबजान खान

7.	मुरादाबाद ग्रामीण	मोहम्मद नासिर
8.	कुंदरकी	जिया उर रहमान
9.	बिलारी	मोहम्मद फहीम इरफान
10.	संभल	इकबाल महमूद
11.	सुआर	अब्दुल्ला आजम खान
12.	चमरौआ	नसीर अहमद खान
13.	रामपुर	मोहम्मद आजम खान
14.	अमरोहा	महबूब अली
15.	सिवालखास	गुलाम मोहम्मद
16.	किठौर	शाहिद मंजूर
17.	मेरठ	रफीक अंसारी
18.	बहेड़ी	अताउर रहमान
19.	भोजीपुरा	शाजिल इस्लाम अंसारी
20.	सीशामऊ	हाजी इरफान सोलंकी
21.	निजामाबाद	आलम बदो
22.	डुमरियागंज	सैयदा खातून
23.	गोपालपुर	नफीस अहमद
24.	कानपुर कैंट	मोहम्मद हसन
25.	मऊ	अब्बास अंसारी
26.	सहारनपुर	आशु मलिक
27.	सिकंदरपुर	जियाउद्दीन रिजवी
28.	लखनऊ वेस्ट	अरमान खान
29.	पटियाली	नादिरा सुल्तान
30.	रामनगर	फरीद महफूज किदवई
31.	मटेरा	मारिया
32.	भदोही	जाहिद बेग
33.	इसौली	मोहम्मद ताहिर खान
34.	मोहम्मदाबाद	सुहैब उर्फ मन्नु अंसारी

इसके अतिरिक्त पंजाब के मलेर कोटला विधान सभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के मोहम्मद जमील उर रहमान चुनाव जीते। उत्तराखंड के लक्सर विधान सभा क्षेत्र से बीएसपी के शहजाद की जीत हुई। वहीं मणिपुर के लिलोंग क्षेत्र से मोहम्मद अब्दुल नसीर, क्षेत्रीगांव से शेख नुरूल हसन और जिरीबाम से मोहम्मद अचाब उद्दीन चुनाव जीते।

टिप्पणी : उत्तर प्रदेश विधान सभा में मुस्लिम विधायकों की संख्या में जो परिवर्तन होता रहा है उसको समझने के लिए 1991 से लेकर अब तक के आंकडे पेश किए जा रहे हैं।

1991 में 197 मुस्लिम उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे जिनमें से 23 जीते। यह संख्या उत्तर प्रदेश विधान सभा के इतिहास में सबसे कम मानी जाती है। यह चुनाव बाबरी मस्जिद आंदोलन के बाद हुए थे, जिनमें हिंदू मतदाताओं का तेजी से ध्रुवीकरण हुआ था। 1993 में 128 मुस्लिम उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे, जिनमें 25 जीते। 1996 में 118 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतरे, जिनमें 36 जीते। 2002 में 199 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतरे, जिनमें 39 जीते। 2007 में 179 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतरे और 51 जीते। 2012 में 230 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतरे और 64 जीते। 2017 में 180 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतरे और मात्र 24 जीते। ■

विधान सभा के चुनाव उर्दू प्रेस की नजर में

हाल ही में संपन्न हुए देश के पांच राज्यों के विधान सभा चुनावों के प्रारंभ से ही उर्दू प्रेस ने भाजपा के खिलाफ माहौल बनाने के लिए जोरदार अभियान चलाया था, मगर चुनाव परिणाम आने के बाद उनके रवैये में नरमी आई है।

लखनऊ से प्रकाशित **जदीद मरकज** (20 मार्च) ने अपने संपादकीय में कहा है कि गांव-गांव दौरा करने वाले पत्रकारों और चुनाव के रूझान का अंदाजा लगाने वाले अनुभवी लोगों और राजनीतिज्ञों के अंदाजे पूरी तरह से गलत साबित हुए हैं और भाजपा ने उत्तर प्रदेश विधान सभा में दो तिहाई बहुमत प्राप्त कर लिया है। इन चुनावों में बेरोजगारी, आसमान छूती महंगाई, आवारा प्शुओं द्वारा फसलों की बर्बादी, कोरोना महामारी के दौरान

बदइंतजामी जैसे मुद्दों को नजरअंदाज करके उत्तर प्रदेश के 52 प्रतिशत हिंदू समाज ने हिंदुत्व और छद्म राष्ट्रवाद के नारों में फंसकर भाजपा को वोट दिए। इस चुनाव में भाजपा की जीत के कारणों में हिंदुत्व के अतिरिक्त मायावती की बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के वोटों का भाजपा में स्थानांतरण, ईवीएम में गड़बड़ी, मुफ्त राशन, भाजपा की भारी-भरकम चुनावी मशीनरी, बेशुमार दौलत और इन सबसे ज्यादा चुनाव आयोग का खुलकर भाजपा के साथ खड़े होना भी महत्त्वपूर्ण है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने तमाम छोटी पिछड़ी जातियों को इकट्ठा करने का जो प्रयास किया था वह विफल रहा। 35-40 सीटें प्रशासन ने भाजपा की झोली में डाल दी। भाजपा के पुराने नेता शत्रुघन सिन्हा ने साफ-साफ आरोप लगाया है कि जिन प्रदेशों में भाजपा की सरकारें थी उनमें ईवीएम में हेराफेरी की गई। बसपा की नेता मायावती भले ही मुसलमानों को दोषी करार दें, मगर वास्तविकता यह है कि उनका जो लगभग दस प्रतिशत वोट कम हुआ वह भाजपा के खाते में गया। सभी ब्राह्मण और राजपूत और तीन चौथाई पिछड़े हिंदुत्व की लहर में बहकर भाजपा के पक्ष में चले गए। इसमें कोई शक नहीं कि मायावती ने जिस तरह से चुनाव लड़ा उससे यह साफ था कि वह अपना वोट बैंक भाजपा को स्थानांतरित करने के लिए कटिबद्ध हैं। इस चुनाव में मुसलमानों ने अपनी पूरी ताकत के साथ एकजुट होकर समाजवादी पार्टी का समर्थन किया। इससे पहले 1984 को छोड़कर मुसलमानों में कभी इतनी एकता पैदा नहीं हुई थी।

इंकलाब (11 मार्च) ने इन चुनावों में भाजपा की विजय का श्रेय भाजपा के अथाह आर्थिक संसाधन, आरएसएस के कैडर का जमीनी समर्थन, गोदी मीडिया का प्रचार और बूथ प्रबंधन को दिया है। समाचारपत्र ने इस बात पर हैरानी प्रकट की है कि कई जिलों जैसे लखीमपुर खीरी जैसे क्षेत्रों में जहां यह समझा जाता था कि भाजपा का सफाया हो जाएगा वहां उसे शानदार सफलता मिली। समाजवादी पार्टी को हालांकि मुसलमानों ने एकजुट होकर समर्थन दिया, मगर वह जनाक्रोश को भुनाने में विफल रही। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के

चुनाव नतीजों ने समाजवादी पार्टी के सत्ता में आने का सपना तोड़ दिया।

रोजनामा सहारा (11 मार्च) का कहना है कि भाजपा का चुनावी प्रबंधन, मुफ्त राशन, सांप्रदायिक आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण के कारण उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सत्ता में आने में विफल रही। पार्टी को इस हार का चिंतन और विश्लेषण करना चाहिए ताकि 2024 के चुनाव में विपक्ष अपनी धाक जमा सके।

अवधनामा (14 मार्च) ने भाजपा की सफलता का श्रेय उसके इस प्रचार को दिया है कि यदि समाजवादी पार्टी सत्ता में आई तो राज्य में फिर से गुंडाराज आ जाएगा। इसलिए दलितों, पिछड़ी जातियों और उच्च जातियों ने एकजुट होकर भाजपा का समर्थन किया और समाजवादी पाटी इस प्रचार का निराकरण करने में पूरी तरह से विफल रही। शुरू से ही मायावती चुनाव लड़ने के बारे में गंभीर नहीं थी। उनका एकमात्र लक्ष्य अपने वोट बैंक को भाजपा के खाते में स्थानांतरित करना था। चुनाव के चौथे चरण में जब अमित शाह ने खुलकर मायावती की प्रशंसा की तो उससे इस बात की पुष्टि हो गई कि बीएसपी इस चुनाव में बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रही है। चुनाव परिणाम वाले दिन ही कर्नाटक उच्च न्यायालय ने जब नौ साल पुराने एक मुकदमे में मायावती के खिलाफ कार्रवाई करने से मना कर दिया तो इस बात की पुष्टि हो गई कि भाजपा ने उन्हें वफादारी का इनाम दे दिया है।

सियासत (13 मार्च) के अनुसार चार राज्यों में भाजपा की जीत से हिंदुत्व की विचारधारा को प्रोत्साहन मिलेगा। इस जीत में प्रशासन, मीडिया का प्रबंधन और ईवीएम की सेटिंग का भी महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। समाचारपत्र ने इस बात का खंडन किया है कि भाजपा की जीत में एआईएमआईएम का भी योगदान है।

सियासत (15 मार्च) ने कांग्रेस के भविष्य पर चिंता प्रकट करते हुए कहा है कि हाल के चुनावों ने यह सिद्ध कर दिया गया है कि कांग्रेस अब राष्ट्रीय दल की बजाय हाशिए पर चली गई है। हैरानी की बात यह है कि इस दुर्गति से कांग्रेसियों ने कोई शिक्षा नहीं ली और उनमें दिन-प्रतिदिन आपसी लड़ाई झगड़े बढ़ते जा रहे हैं।

सालार (13 मार्च) ने इस बात पर जोर दिया है कि सरकार और भाजपा द्वारा प्रायोजित मीडिया भाजपा की सफलता को जानबूझकर बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश में योगी मंत्रिमंडल के एक दर्जन मंत्री चुनाव हार गए जिनमें उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हैं। कट्टर हिंदुत्व राजनीति के कई पोस्टर बॉय भी अपनी सीट तक नहीं बचा पाए। इनमें संगीत सोम, रघुवेंद्र सिंह, सुरेश राणा, आनंद स्वरूप शुक्ला, उमेश मलिक आदि शामिल थे। सुरेश राणा राष्ट्रीय लोक दल के उम्मीदवार अशरफ अली खान से दस हजार से भी ज्यादा वोटों से चुनाव हारे हैं। संगीत सोम को सरधना सीट से हार का सामना करना पड़ा है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार समाजवादी पाटी के किसी उम्मीदवार ने इस सीट से जीत हासिल की है। कैराना में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने घर-घर जाकर वोट मांगे थे, मगर इसके बावजूद भाजपा की उम्मीदवार मृगांका सिंह चुनाव हार गईं और उन्हें समाजवादी पार्टी के नाहिद हुसैन ने 26 हजार वोटों के अंतर से हराया।

सालार (12 मार्च) ने अपने संपादकीय में भाजपा की जीत की आलोचना करते हुए कहा है कि जिस तरह से देश के चार राज्यों में भाजपा सत्ता में आई है उसके कारण लोकतंत्र का भविष्य इस देश में अंधकारमय हो गया है। समाचारपत्र का कहना है कि सबसे ज्यादा दुर्गति कांग्रस की हुई है वह आज भी इतनी आत्ममुग्ध है कि उसने अपनी हार का चिंतन-मनन करने की भी जरूरत नहीं समझी।

मुंबई उर्दू न्यूज (11 मार्च) ने उत्तर प्रदेश के चुनाव का विश्लेषण करते हुए इस बात पर हैरानी प्रकट की है कि इन चुनावों के बारे में सभी विशेषज्ञों के पूर्वानुमान धाराशाई हो गए हैं और बुलडोजर सरकार फिर सत्ता में आ गई है। समाचारपत्र ने इसके लिए मीडिया प्रबंधन, विपुल आर्थिक साधन, ईवीएम की सेटिंग और विपक्षी दलों द्वारा भाजपा के चुनावी प्रचार का सफलतापूर्वक निराकरण न किए जाने को जिम्मेवार ठहराया है। योगी आदित्यनाथ इस बात को भलीभांति जानते हैं कि उनकी चुनावी सफलता में बुलडोजर कार्ड की बजाय ईवीएम कार्ड का ज्यादा हाथ है। भाजपा भले ही कुछ भी दावा करे, मगर इन चुनाव परिणामों को देखकर फिल्म अभिनेता अनिल कपूर और जूही चावला की फिल्म बादशाह की याद आतो है। जिसमें चुनाव, गुंडागर्दी से जीता गया था और इस जीत में जनता का कोई हाथ नहीं था।

मुंबई उर्दू न्यूज (11 मार्च) में महाराष्ट्र वेल्फेयर पार्टी ऑफ इंडिया जो कि जमात-ए-इस्लामी का राजनीतिक विंग है के अध्यक्ष सलीम शेख का एक लेख प्रकाशित हुआ है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि अभी तक मुसलमानों को सभी सेक्युलर पार्टियों और उसके नेताओं ने छला है। इसलिए मुसलमानों को एकजुट होकर अपने नेतृत्व को विकसित करना चाहिए। वरना उनका नामोनिशान मिट जाएगा।

मुंबई उर्दू न्यूज (9 मार्च) ने एक लेख में कहा है कि भाजपा और योगी आदित्यनाथ ने गुडों की मदद से जो माहौल बनाया था उसके कारण विपक्षी मतदाता मतदान केंद्रों में जाकर मतदान करने में विफल रहे हैं।

हमारा समाज (13 मार्च) ने अपने संपादकीय में उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजों पर हैरानी प्रकट की है और कहा है कि भाजपा को पुनः सत्ता में लाने में उस लाभार्थी वर्ग का सबसे बड़ा हाथ है, जिन्हें मुफ्त राशन और नकद सहायता मिली। दूसरा कारण मायावती का चुनावी अभियान से उदासीन रहना और अपने वोट बैंक को भाजपा में स्थानांतरित करना है। समाजवादी पार्टी ने हालांकि अपनी शक्ति तो बढ़ा ली है, मगर सत्ता में आने में विफल रही है। इसका कारण उसका घटिया चुनावी प्रबंधन और प्रचारतंत्र है। कांग्रेस की विफलत का सबसे बड़ा कारण यह है कि वह जनता में इस बात का भरोसा पैदा करने में विफल रही कि वह भाजपा का विकल्प बन सकती है।

इत्तेमाद (11 मार्च) ने अपने संपादकीय में कहा है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के पुनः सत्ता में आने का अर्थ यह है कि देश में हिंदुत्व की जड़ें और भी मजबूत हो गई हैं। अब 2024 में मोदी को पुनः सत्ता में आने में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर अखिलेश यादव के साथ बीएसपी और कांग्रेस होते तो शायद स्थिति दूसरी होती। अब इन चुनावी नतोजों के बाद कांग्रेस को अपनी दुकान बंद कर देनी चाहिए। वह आपसी गुटबाजी में बुरी तरह से फंस गई है और अपने रास्ते से भटक गई है। उसकी हालत एक ऐसे घोड़े की हो गई है जिसकी लगाम थामने की हिम्मत किसी में नहीं है। समाचारपत्र ने कहा है कि मोदी योगी को मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहते थे, मगर संघ के समर्थन के कारण वे अपनी योजना में सफल नहीं हो पाए। उत्तर प्रदेश के चुनाव सिर्फ चुनाव ही नहीं बल्कि वह एक संपूर्ण राजनीतिक योजना थी, जिसमं प्रशासनिक मशीनरी ने भी पूरी तरह से साथ दिया। जहां तक पंजाब का संबंध है वहां पर आम आदमी पार्टी की जीत के कारण नए युग का श्रीगणेश हुआ है।

भागलपुर बम धमाके में 14 मरे

इंकलाब (4 मार्च) के अनुसार भागलपुर के तातारपुर थाना क्षेत्र के काजवली चक मोहल्ले में पुलिस थाने से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर हुए बम धमाकों में कम-से-कम 14 व्यक्ति मौके पर मारे गए और दर्जनों घायल हो गए। पुलिस का दावा है कि बम बनाने के दौरान यह धमाका हुआ है। इस धमाके के कारण कम-से-कम चार मकान पूरी तरह से तबाह हो गए। पुलिस को मलबा हटाते समय वहां से कई किलोग्राम बारूद और लोहे की कीलें मिली हैं। इस घटना की पुलिस विभिन्न पहलुओं से जांच कर रही है। जांच के लिए एफएसएल टीम को विशेष रूप से बुलाया गया है। पुलिस महानिदेशक के आदेश पर तातारपुर थाने के प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस का दावा है कि ये बम अवैध रूप से बनाए जा रहे थे। इस संदर्भ में हालांकि स्थानीय पुलिस को कई बार शिकायतें प्राप्त हुई थीं, मगर उन्होंने इस संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की। बिहार के मुख्यमंत्री ने इस धमाके की उच्चस्तरीय जांच करने का निर्देश दिया है। हालांकि पुलिस ने यह दावा किया है कि बम बनाने की यह फैक्ट्री कई दशकों से वहां चल रही थी और वहां पटाखे तैयार हो रहे थे, मगर पुलिस के इस दावे में सबसे बड़ा झोल यह है कि आतिशबाजो के लिए जो पटाखे तैयार किए जाते हैं उनमें लोहे की कीलों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। लोहे की कीलों का इस्तेमाल सिर्फ घातक बम बनाने में ही होता है ताकि इन कीलों के लगने से लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में मर सकें। जिस मोहल्ले में यह धमाका हुआ है वह बहुत ही घनत्व वाला है। इसलिए घायलों और मृतकों को इस क्षेत्र से निकालने में काफी परेशानी हुई।

भागलपुर की पूर्व उपमहापौर प्रीति शेखर का कहना है कि इस तरह के धमाके इससे पूर्व भी इस क्षेत्र में होते रहे हैं, मगर पुलिस ने हर बार मामलों को दबा दिया। उन्होंने कहा कि वे पुलिस के दावे से संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने मांग की कि इस कांड की निष्पक्ष जांच करवाई जाए ताकि बम बनाने वालों की साजिश और उनके मंसूबों का पर्दाफाश हो सके। उन्होंने कहा कि इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि जो लोग यह धंधा कर रहे थे उनका संबंध किस संगठन से था। मुख्य मंत्री ने इस घटना की जांच का कार्य एटीएस को सौंप दिया है और उसने इस संबंध में छह मुकदमे दर्ज किए हैं। बताया जाता है कि यह जमीन और मकान मोहम्मद आजाद का है। इस स्थान पर रहने वाले कई लोग धमाके में मारे गए हैं। मोहम्मद आजाद का यह दावा है कि उसने यह मकान किराए पर दिया हुआ था और उसका इस मामले से कोई संबंध नहीं है। इससे पूर्व भी इसी स्थान पर 2002, 2008 और 2021 में भी ऐसे ही धमाके हुए थे।

बिहार विधान सभा में हंगामा

इंकलाब (12 मार्च) के अनुसार बिहार विधान सभा में उस समय जबर्दस्त हंगामा हुआ जब जुमा की नमाज के समय भी विधान सभा के अध्यक्ष ने विधान सभा की कार्रवाई के समय में वृद्धि कर दी। बिहार विधान सभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने जब सदन की कार्रवाई को जारी रखने का निर्देश दिया तो विपक्ष ने विधान सभा के बेल में जाकर इसके खिलाफ विरोध प्रकट किया और कहा कि विधान सभा के नियमों के अनुसार जुमा को साढ़े बारह बजे विधान सभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया जाता है ताकि लोग नमाज अदा कर सकें। जब विधान सभा अध्यक्ष ने एआईएमआईएम के विधायक अख्तरूल ईमान और राष्ट्रीय जनता दल के विधायक अख्तर शाहीन की इस मांग को अस्वीकार कर दिया तो उनका समर्थन कांग्रेस के विधायक विजय शंकर दुबे ने किया और इस बात पर दु:ख प्रकट की कि विधान सभा अध्यक्ष सभी नियमों को ताक पर रखकर नई परंपरा की शुरुआत कर रहे हैं। इसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। जवाब में भाजपा के सदस्यों ने भी नारे लगाए। अध्यक्ष ने कहा कि जो लोग नमाज पढ़ना चाहें वे सदन से बाहर जाकर नमाज पढ़ सकते हैं। इस पर काफी समय तक हंगामा होता रहा। हंगामे के बाद सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। भाजपा के विधायक पवन जायसवाल ने कहा कि धर्म के आधार पर सदन की कार्रवाई को चलाया जाना सरासर गलत है। इस पर उनकी विपक्षी विधायकों से झड़पें भी हुईं।

इंकलाब (8 मार्च) के अनुसार विधान सभा में उस समय भी भारी हंगामा हुआ जब भाजपा के विधायक कुमार शैलेंद्र ने अल्पसंख्यकों को देश विरोधी बताया। विपक्षी दलों ने बेल में जाकर नारे लगाए और सदन का बहिष्कार किया। उनकी मांग थी कि कुमार शैलेंद्र अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगें, मगर उन्होंने माफी मांगने से इंकार कर दिया। बाद में सीपीआईएम और एआईएमआईएम के विधायक अख्तरूल ईमान ने एक संयुक्त पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए विधान सभा अध्यक्ष से मांग की कि अल्पसंख्यकों को देशद्रोही बताने वाले भाजपा विधायक को सदन से निलंबित किया जाए। क्योंकि जो परंपरा शुरू की जा रही है वह अल्पसंख्यक विरोधी है। इसे सहन नहीं किया जा सकता।

निजामुद्दीन स्थित तब्लीगी मरकज अभी नहीं खुलेगा

रोजनामा सहारा (5 मार्च) के अनुसार गृहमंत्रालय ने बस्ती निजामुद्दीन स्थित तब्लीगी जमात के मरकज को खोलने का दिल्ली उच्च न्यायालय में विरोध किया है। मार्च 2020 में कोरोना महामारी के दौरान इस मरकज में तब्लीगी जमात का एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। बाद में महामारी फैलाने के आरोप में तब्लीगी जमात से संबंधित अनेक लोगों को देश के विभिन्न भागों स गिरफ्तार किया गया और इस मरकज को सील कर दिया गया। तब से यह मरकज बंद है। यह मरकज एक मस्जिद में स्थित है जिसे बंगलेवाली मस्जिद कहा जाता है। इसमें एक मदरसा भी है। इसी महीने तब्लीगी जमात ने दिल्ली उच्च न्यायालय से यह मांग की थी कि रमजान और शब-ए-बारात को देखते हुए इस मरकज को खाल दिया जाए, मगर गृहमंत्रालय ने इसका विरोध किया है। बाद में उच्च न्यायालय ने शब-ए-बारात के पर्व को मनाने के लिए तब्लीगी जमात को मरकज खोलने की अनुमति दे दी। सरकारी वकील का कहना है कि यह मस्जिद केस प्रॉपर्टी है और याचिकाकर्ता के पास इसे पुनः खोलने की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है। पहले ही न्यायालय ने कुछ लोगों को इस मरकज की देखभाल करने की अनुमति दे दी है। जबकि तब्लीगी जमात के वकील ने कहा कि दिल्ली में कोरोना महामारी के दौरान लगाए गए सभी प्रतिबंधों को हटाया जा चुका है। इसलिए इसकी भी सील खोल देनी चाहिए।

हमारा समाज (15 मार्च) ने यह दावा किया है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि इस मरकज की सील खोल दी जाए। क्योंकि इसको कोरोना महामारी के आधार पर बंद किया गया था। न्यायालय ने उन्हें यह निर्देश दिया है कि वे इस संबंध में स्थानीय पुलिस से संपर्क करें।

देश के विभिन्न समाचारपत्रों में अनक लेख प्रकाशित हुए हैं, जिनमें तब्लीगी जमात में तालाबंदी को जारी रखने की आलोचना की गई है।

मुंबई उर्दू न्यूज (12 मार्च) में एक लेख प्रकाशित किया गया है, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि सरकार जानबूझकर मुसलमानों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही है और उन्हें इस मरकज में नमाज अदा करने की अनुमति नहीं दे रही है जो कि उनका बुनियादी अधिकार है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार की नीतियां मुस्लिम विरोधी हैं इसलिए वह जानबूझकर इस्लाम के प्रचार-प्रसार में रूकावट डाल रही है।

इंकलाब (15 मार्च) के अनुसार केंद्र सरकार बस्ती निजामुद्दीन स्थित तब्लीगी जमात मरकज को खोलने की अनुमति न देने की जिद पर अड़ी हुई है। उसने पुनः उच्च न्यायालय में कहा है कि पहले ही न्यायालय इस मस्जिद में 50 लोगों को नमाज पढ़ने की अनुमति दे चुकी है। इसलिए पूरे मरकज को नहीं खोला जा सकता।

रोजनामा सहारा (11 मार्च) के अनुसार एक मुस्लिम नेता उबैद खान ने केंद्र सरकार पर मुस्लिम विरोधी नीति अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि देश की विभिन्न अदालतों में सरकार ने तब्लीगी जमात के कार्यकर्ताओं के खिलाफ जो दर्जनों मुकदमे दायर किए थे वे सभी खारिज हुए हैं। क्योंकि अदालत ने इस मामले में तब्लीगी जमात को दोषी नहीं पाया है। इसके बावजूद जानबूझकर मुसलमानों को परेशान करने के लिए इस तब्लीगी मरकज को नहीं खोला जा रहा है।

विश्व

पाकिस्तान में शियाओं पर कहर

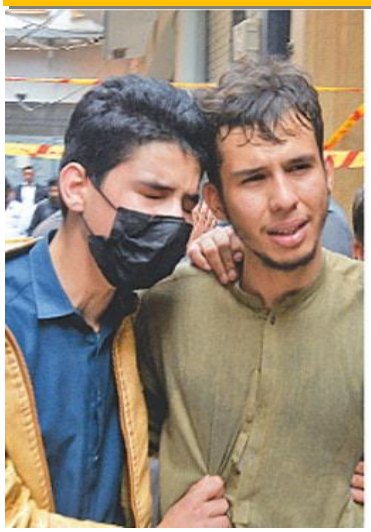

मुंबई उर्दू न्यूज (5 मार्च) के अनुसार पेशावर में शिया मस्जिद में आत्मघाती हमले में मारे जाने वाले नमाजियों की संख्या 62 को भी पार कर गई है। इसके अतिरिक्त 200 से भी अधिक घायल गंभीर अवस्था में नगर के विभिन्न अस्पतालों में पड़े हुए हैं।

सियासत (5 मार्च) के अनुसार यह धमाका पेशावर के किस्सा ख्वानी बाजार के शिया जामा मस्जिद में हुआ है। पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद अहमद ने कहा है कि इस हमले के पीछे आत्मघाती दस्ते का हाथ है, जिससे संबंधित तीन फिदायीन मस्जिद में घुसे और उन्होंने स्वयं को अपने शरीर के साथ बंधे हुए बमों स उड़ा लिया। उन्होंने कहा कि इस हमले से पूर्व सुरक्षा एजेंसियों ने ऐसे किसी हमले का संकेत नहीं दिया था। जबकि पेशावर पुलिस का दावा है कि आक्रमणकारियों ने जब मस्जिद के अंदर घुसने का प्रयास किया तो वहां पर तैनात पुलिस अधिकारियों ने उन्हें रोका। इस पर उन्होंने उन दोनों पुलिस अधिकारियों को गोली से उड़ा दिया। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार प्रारंभ में इस धमाके के पीछे एक पड़ोसी देश के एजेंटों का हाथ बताया गया था, मगर बाद में **मुंबई उर्दू न्यूज** (6 मार्च) के अनुसार इस हमले के पीछे जिहादी संगठन इस्लामिक स्टेट ने अपना हाथ होना स्वीकार किया है। गृह मंत्री शेख रसीद ने दावा किया है कि पाकिस्तान पुलिस के गुप्तचरों ने इस धमाके के जिम्मेवारों का पता लगा लिया है और उन्हें शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार बाद में पांच संदिग्ध व्यक्तियों को इस सिलसिले में पुलिस ने हिरासत में लिया है। अभी तक गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के बारे में पुलिस ने कोई जानकारी नहीं दी है।

इंकलाब (6 मार्च) के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस घटना पर चिंता प्रकट की है और दुनिया के विभिन्न देशों से अपील की है कि वे इस घटना के जिम्मेवार संगठनों और उससे जुड़े हुए आरोपियों की गिरफ्तारी में पाकिस्तान सरकार की सहायता करें।

इंकलाब (7 मार्च) के अनुसार इस घटना के बाद पाकिस्तान के विभिन्न नगरों में शियाओं ने विरोध प्रदर्शन किए और इस बात की निंदा की

कि पाकिस्तान की सरकार उन्हें सुरक्षा प्रदान करने में विफल रही है। पाकिस्तान में कई ऐसे संगठन सक्रिय हैं जो सुनियोजित ढंग से शियाओं और उनके इमामबाड़ों पर हमले करते रहते हैं। शिया संगठनों ने इस संदर्भ में तालिबान, जमात-उल-अहरार, सिपाह-ए-सहाबा और लश्कर-ए-झंगवी का उल्लेख किया है। पाकिस्तान में कराची, हैदराबाद, लरकाना, कंधकोट, लाहौर, मुल्तान, गुजरांवाला, पाराचिनार और मुजफ्फराबाद में भी विरोध प्रदर्शन हुए हैं।

सियासत (9 मार्च) ने अपने संपादकीय में पाकिस्तान में मुसलमानों के विभिन्न संप्रदायों में बढ़ती हुई हिंसा पर चिंता प्रकट की है और कहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद शियाओं के लिए खतरा बढ़ गया है। गत दो वर्षों में पाकिस्तान में हुए धमाकों में 200 से अधिक शिया मारे जा चुके हैं। अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट के आतंकवादी सक्रिय हैं और वे शियाओं को अपना निशाना बना रहे हैं। इस्लामिक स्टेट भले ही मुस्लिम संगठन होने का दावा करे, मगर वह अपना निशाना चुन-चुनकर मुसलमानों को ही बना रही है। विश्लेषकों का कहना है कि इस्लामिक स्टेट पूरे पाकिस्तान में अपने पैर पसार चुकी है और पाकिस्तान के शिया उसके निशाने पर हैं।

समाचारपत्र का कहना है कि पाकिस्तान के दो अन्य कट्टर सुन्नी संगठन अहले सुन्नत वल जमात और तहरीक-ए-लब्बैक भी शिया विरोधी अभियान में सक्रिय भाग ले रहे हैं। जब पाकिस्तान का गठन किया गया था तो यह दावा किया गया था कि यह एक इस्लामिक देश है, जिसमें सभी मुसलमान अमन-चैन से रह सकेंगे, मगर पाकिस्तान बनते ही पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान को दिनदहाड़े मार दिया गया और आज तक उनके हत्यारे का पता नहीं लगाया जा सका। पाकिस्तान को परमाणु शक्ति बनाने वाले जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पर लटका दिया गया। सऊदी अरब के सहयोग से खिलाफत इस्लामिया को पुनर्जीवित करने की मांग करने वाले जनरल जिया-उल-हक के विमान में कुछ रहस्यमयी शक्तियों ने बम रखकर उनका खात्मा कर दिया। पाकिस्तान को मजबूत बनाने वाले नवाज शरीफ को देश छोड़कर भागना पड़ा है। पाकिस्तान में मुसलमानों के विभिन्न संप्रदायों में जो तनाव बढ़ रहा है वह इस्लाम और पाकिस्तान दोनों के लिए बहुत बड़ा खतरा है।

चीन के रक्षा बजट में वृद्धि

इंकलाब (12 मार्च) के अनुसार चीन ने अपने रक्षा बजट में 229 बिलियन डॉलर की वृद्धि कर दी है। इससे साफ है कि चीन अपने आप को सैन्य दृष्टि से पहले से भी अधिक मजबूत बना रहा है और वह न सिर्फ पड़ोसियों बल्कि अमेरिका को भी चुनौती देने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका क बाद चीन दुनिया में सबसे ज्यादा धनराशि अपनी सेना पर खर्च कर रहा है और उसके नियमित सैनिकों की संख्या 30 लाख है जो कि विश्व में

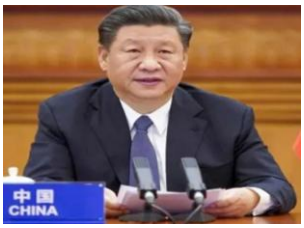

सबसे बड़ी सेना मानी जाती है। इसके अतिरिक्त यह सेना विश्व के आधुनिकतम अस्त्र-शस्त्रों से लैश है, जिनमें युद्धविमान, अत्याधुनिक प्रक्षेपास्त्र, परमाणु सशस्त्रों से लैश पनडुब्बियां और विमान वाहक जलयान आदि शामिल हैं।

कोरोना की महामारी के कारण चीन की अर्थव्यवस्था को हालांकि भारी झटका लगा है, मगर इसके बावजूद वह निरंतर अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने और सेना को अधिकतम अस्त्र-शस्त्र से

लैश करने में लगा हुआ है। चीन अस्त्र-शस्त्रों के मामल में आत्मनिर्भर है और वहां की शासन व्यवस्था में पीपुल्स लिब्रेशन आर्मी की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। चीन के राष्ट्रपति और वहां की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख शी जिनपिंग इसके भी प्रमुख हैं। सैनिक विशेषज्ञों का कहना है कि चीन ताइवान को हड़पने और लद्दाख एवं अरूणाचल में पैर पसारने का प्रयास कर रहा है। इसके अतिरिक्त वह भारत को घेरने के लिए मोतियों की माला की सैनिक संधियों को लागू कर रहा है। हाल ही में उसने श्रीलंका के साथ अनेक सैन्य संधियां की हैं। रूस के साथ हाल ही में उसके संबंधों में सुधार होने के बाद उसकी विस्तारवादी नीतियों में और भी वृद्धि होने की संभावना व्यक्त की जा रही है।

बांग्लादेश के बिहारी मुसलमानों के कल्याण के लिए योजना

रोजनामा सहारा (8 मार्च) बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने यह घोषणा की है कि उनकी सरकार बांगलादेश में रहने वाले उर्दू भाषी मुसलमान जो कि वहां पर बिहारी कहलाते हैं के कल्याण की अनेक योजनाएं मानवीय आधार पर बना रही है। बांग्लादेश समाचार सेवा के अनुसार देश के विभाजन के समय लाखों की संख्या में उर्दू भाषी मुसलमान भारत से भागकर पूर्वी पाकिस्तान में आबाद हुए थे। बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में इन लोगों ने स्थानीय बंगालियों का विरोध किया और पाकिस्तान का डटकर समर्थन किया। जब ढाका में 90 हजार पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था तो इन उर्दू भाषी मुसलमानों को इस बात की आशा थी कि उन्हें पाकिस्तान सरकार स्वीकार करेगी और उन्हें पश्चिमी पाकिस्तान में बसने की अनुमति दे देगी, मगर पाकिस्तान सरकार ने उन्हें अपने देश में घुसने की अनुमति नहीं दी और वे बांग्लादेश में ही विभिन्न शिविरों में स्थानीय लोगों से अलग-थलग रह रहे हैं। उनकी आर्थिक स्थिति दिन-प्रतिदिन खराब होती जा रही है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से उन्हें कुछ सहायता प्रदान की जाती है, मगर अभी तक वे आत्मनिर्भर नहीं हो सके हैं।

प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि इस समय बांग्लादेश में ऐसे उर्दू भाषी मुसलमानों की संख्या 15 से 20 लाख बताई जाती है। उन्होंने कहा कि 1971 के बाद ऐसे मुसलमानों की कई नई पीढ़ियां पैदा हो चुकी हैं। वे बहुत मेहनती हैं और उनमें काम करने की भी भावना है। बांग्लादेश सरकार यह चाहती है कि मानवीय सहानुभूति के नाते उन्हें रोजगार की सुविधाएं मुहैया की जाएं ताकि वे बांग्लादेश में सही ढंग से रह सकें। इस समय देश के 13 जिलों में बने हुए पुनर्वास शिविरों में वे गत कई दशकों से रह रहे हैं। राजधानी ढाका के जिनेवा कैंप में रहने वाले ऐसे बिहारी मुसलमानों की संख्या दो लाख के लगभग बताई जाती है। अभी तक वे पूर्णतः संयुक्त राष्ट्र संघ से मिलने वाले भत्ते पर ही निर्भर हैं।

सिराजुद्दीन हक्कानी का अज्ञातवास समाप्त

सियासत (7 मार्च) के अनुसार अफगानिस्तान की सबसे विवादित हस्ती सिराजुद्दीन हक्कानी पहली बार काबुल में एक सार्वजनिक समारोह में नजर आए। उन्होंने नेशनल पुलिस एकेडमी की पासिंग आउट परेड को संबोधित किया। उनके साथ अफगानिस्तान के उपप्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर भी थे। उन्होंन इस अवसर पर पहली बार पुलिस कैडेटों और मीडिया को भी संबोधित किया। गौरतलब है कि हक्कानी को सबसे खतरनाक आतंकवादी माना जाता है। वे खूंखार संगठन हक्कानी नेटवर्क के प्रमुख हैं और उनके ऊपर अमेरिका ने एक करोड़ डॉलर के इनाम की घोषणा कर रखी है। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद हालांकि उन्हें नई सरकार में विदेश मंत्री बनाया गया था, मगर वे कभी भी सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दिए। कहा जाता है कि अफगान सरकार को इस बात का भय है कि उन्हें अमेरिका के एजेंट अपना निशाना बना सकते हैं। क्योंकि वे अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों की सूची में मोस्ट वांटेड आतंकवादी हैं।

पश्चिमी देशों में अस्त्र–शस्त्र खरीदने की होड़

इंकलाब (15 मार्च) के अनुसार दुनिया भर के विभिन्न देशों में अस्त्र-शस्त्रों के भंडार रखने की होड़ शुरू हो गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 2021 के बीच अस्त्र-शस्त्र के कारोबार में पांच प्रतिशत की कमी देखी गई थी, मगर इसके बावजूद यूरोपीय देशों में हथियारों की खरीदारी में 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सबसे ज्यादा हथियार यूरोपीय देशों ने खरीदे हैं। यूरोपीय देश अपनी रक्षा बजटों में भारी वृद्धि कर रहे हैं और इस लक्ष्य से वे विदेशों से भारी संख्या में अस्त्र-शस्त्र खरीद रहे हैं। सबसे ज्यादा हथियारों का कारोबार अमेरिका करता ह। इसके बाद दूसरे नंबर पर रूस है। हालांकि हाल ही में रूस के हथियारों के कारोबार में 26 प्रतिशत की गिरावट आई है। इसका मूल कारण भारत और वियतनाम की ओर से रूसी अस्त्र-शस्त्रों की खरीदारी में कटौती है।

विश्व के हथियार कारोबारियों का अनुमान है कि भारत आने वाले दिनों में रूस से भारी मात्रा में अस्त्र-शस्त्र खरीद सकता है। हाल ही में यूरोप के कई देशों ने यह घोषणा की है कि विश्व के बदलते हुए परिदृश्य में उनके लिए रक्षा बजट में वृद्धि करना अनिवार्य हो गया है। जर्मनी ने हाल ही में अपने रक्षा बजट में भारी वृद्धि की है। डेनमार्क और स्वीडन ने भी हथियारों की खरीद में वद्धि करने का संकेत दिया है। इसके कारण यूरोपीय देशों की विश्व के हथियारों के बाजार में भागीदारी में दस प्रतिशत की वृद्धि हुई है और अभी उसमें और वृद्धि होने की संभावना है। प्रत्येक देश विदेशों से अपने हथियार गुप्त रूप से खरीदता है इसलिए इस बात का दावा करना संभव नहीं है कि कौन सा देश हथियारों की खरीद पर कितनी धनराशि खर्च कर रहा है।

पश्चिम एशिया

सऊदी अरब में 81 लोगों को मृत्युदंड

इत्तेमाद (13 मार्च) के अनुसार सऊदी अरब के हाल के इतिहास में पहली बार एक ही दिन में 81 व्यक्तियों को सजा-ए-मौत दी गई है। सऊदी अरब की परंपरा के अनुसार इन सभी आरोपियों को नगर की सबसे बड़ी मस्जिद के बाहर जल्लादों ने तलवार से सार्वजनिक रूप से मौत के घाट उतारा है। सऊदी अरब की सरकारी प्रेस एजेंसी ने यह दावा किया है कि जिन लोगों को मौत की सजा दी गई है वे तस्कर और मासूम लोगों के हत्यारे थे। हालांकि अन्य सूत्रों के अनुसार जिन लोगों को मौत की सजा दी गई है उनमें से काफी का संबंध अलकायदा और आईएसआईएस एवं यमनी हूती विद्रोहियों से है।

सूत्रों के अनुसार जिन लोगों को मौत की सजा दी गई है उनमें से अधिकांश शिया हैं और वे काफी समय से सऊदी अरब क सुन्नी शासन के खिलाफ अभियान चला रहे थे। उनको सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। ईरान क विदेश मंत्रालय के अनुसार सऊदी सरकार द्वारा शियाओं के उत्पीड़न के खिलाफ विरोध प्रकट करते हुए ईरान ने सऊदी अरब के साथ होने वाली प्रस्तावित वार्ता को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया है।

सऊदी प्रेस एजेंसी ने दावा किया है कि जिन लोगों को मौत की सजा दी गई है उन्हं अदालत में उनका पक्ष रखने के लिए सरकार की ओर से कानूनी सहायता प्रदान की गई थी। जिन लोगों को मौत की सजा दी गई है उनमें से काफी का संबंध सऊदी अरब की प्रशासकीय सेवाओं से था। सऊदी सरकार के एक प्रवक्ता ने यह दावा किया है कि सऊदी अरब आतंकवाद और दहशतगर्दी को किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेगा और उसे सख्ती से दबा दिया जाएगा। क्योंकि इन रूझानों के कारण सारे विश्व की शांति और स्थिरता खतरे में पड़ सकती है।

सरकारी सूत्रों के अनुसार इससे पूर्व 2016 में एक ही दिन 47 लोगों की तलवार से गर्दन काटी गई थी। इन सभी लोगों का संबंध सऊदी अरब में सक्रिय शिया असंतुष्ट गुट से था। इन्होंने सऊदी अरब में सरकार क खिलाफ विरोध प्रदर्शन

किए था। इस घटना के बाद सऊदी अरब और ईरान के बीच संबंध बहुत तनावपूर्ण हो गए थे और तेहरान में सऊदी दूतावास पर भीड़ ने हमला करके उसे आग लगा दी थी। तब से दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध बहाल नहीं हुए हैं। इसके बाद 2019 में 37 शिया विद्रोहियों को एक साथ एक ही दिन मौत की सजा दी गई थी। इन पर आतंकवादी गतिविधियों में भाग लेने का आरोप लगाया गया था।

रोजनामा सहारा (12 मार्च) के अनुसार अतिवादी इस्लामिक संगठन इस्लामिक स्टेट ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि अमेरिकी हमले में उसके अमीर-ए-आला अबू इब्राहिम अल-हाशिमी अल कुरैशी मारा गया है। उसका उत्तराधिकारी अबू अल-हसन अल-हाशिमी अल-कुरैशी को नियुक्त किया गया है। गौरतलब है कि इस आतंकवादी संगठन का गठन 2014 में किया गया था। इससे पूर्व इसके दो खलीफा मारे जा चुके हैं। इस्लामिक स्टेट के प्रवक्ता ने कहा कि अबू अल-हसन मुसलमानों के अमीर-ए-आला और खलीफा अल-मुस्लिमीन होगा। हालांकि नए अमीर के बारे में कोई जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं है। बताया जाता है कि अबू इब्राहिम ने अपने जीवन काल में ही उसे अपना उत्तराधिकारी मनोनीत कर दिया था। इस्लामिक स्टेट का पहला खलीफा अबू बकर अल-बगदादी था, जिसे अमेरिकी सेना ने अक्टूबर 2019 में मार दिया था।

सऊदी अरब में कोरोना से संबंधित प्रतिबंध समाप्त

इत्तेमाद (7 मार्च) के अनुसार कोरोना के घटते केसों के कारण सऊदी सरकार ने मक्का और मदीना की यात्रा पर लगाए गए सभी प्रतिबंधों को हटाने की घोषणा की है। हालांकि मक्का और मदीना की मस्जिद-ए-नबवी में नमाज अदा करने के इच्छुकों को हज मंत्रालय से पूर्वानुमति लेनी होगी। सऊदी सरकार के अनुसार मक्का की परिक्रमा और अंदर और बाहर के क्षेत्र में सामाजिक दूरी के सभी स्टीकर हटा दिए गए हैं। पिछले जुमा को इन दोनों पवित्र स्थानों पर 5 लाख लोगों ने जुमा की नमाज अदा की। इसके अतिरिक्त अब सऊदी अरब आने वाले यात्रियों को आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाने

की जरूरत नहीं होगी, मगर उन्हीं लोगों को इन पवित्र स्थानों पर दाखिल होने की अनुमति होगी जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन लगवा रखी होगी और उन्हें मास्क पहनना होगा। सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ इक्ट्ठा होने पर जो प्रतिबंध लगाए गए थे उन्हें भी हटा लिया गया है। इसके अतिरिक्त सऊदी सरकार ने 17 देशों की एयरलाइंस पर लगाए गए सभी प्रतिबंधों को हटाने की भी घोषणा की है, मगर उमरा और हजरत मोहम्मद के मजार पर नमाज पढने के लिए पूर्वानुमति लेनी होगी। यह कदम भीड़ को रोकने के लिए उठाया गया है। सभी यात्रियों को बीमा की सुविधाएं भी सरकार ने प्रदान करने की घोषणा की है।

इजरायली संसद में फिलिस्तीनियों को नागरिकता न देने का कानून पारित

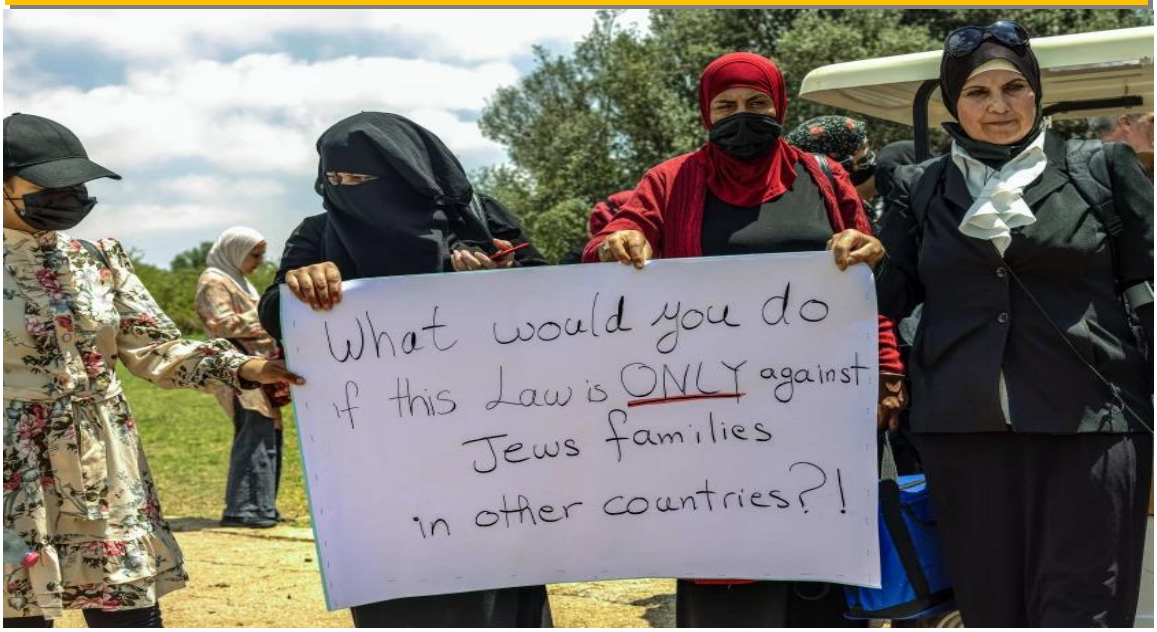

इंकलाब (12 मार्च) के अनुसार इजरायली संसद ने एक कानून पास किया है जिसके तहत पश्चिमी किनारा और गाजा से संबंध रखने वाले फिलिस्तीनियों को इजरायल की नागरिकता प्राप्त करने और वहां पर रहने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इजरायली संसद में इस कानून के पक्ष में 45 और विराध में 15 मत प्राप्त हुए। इजरायल ने दावा किया है कि यह कानून सुरक्षा कारणों को देखते हुए पारित किया गया है। हालांकि विश्लेषकों का दावा है कि इजरायल का इरादा इन क्षेत्रों में रहने वाले फिलिस्तीनियों को वहां से बेदखल करके उनके स्थान पर यहूदियों को आबाद करना है।

इजरायली समाचारपत्र ने एक समाचार प्रकाशित किया है जिसके अनुसार पश्चिमी किनारे पर एक नई यहूदी बस्ती बसाई जा रही है। इसे अराद के क्षेत्र में बसाया जा रहा है जो कि मिस्र सीमा के समीप स्थित है। इस नई कॉलोनी में 20 हजार नए फ्लैटों का निर्माण किया जाएगा, जिनमें एक लाख नए यहूदी रह सकेंगे। वहां पर मेडिकल सेंटर, शॉपिंग सेंटर, स्कूल और अस्पताल आदि सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। फिलिस्तीन क अतिवादी इस्लामिक संगठन हमास ने इस नई इजरायली योजना का विरोध किया है और उसे संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्तावों का उल्लंघन बताया है।

सियासत (13 मार्च) ने एक संपादकीय में इजरायल की निंदा की है और कहा है कि विश्व का सारा ध्यान यूक्रेन क घटनाक्रम की ओर लगा हुआ है। इसका लाभ उठाकर इजरायल फिलिस्तीनियों के मानवाधिकारों का खुलेआम हनन कर रहा है और संयुक्त राष्ट्र संघ मूकदर्शक बनकर इसे देख रहा है। समाचारपत्र ने अरब देशों से अनुरोध किया है कि वे इजरायल के बढ़ते हुए खतरे को समझें और आपसी मतभेद भुलाकर उसका विरोध करें।

तुर्की इजरायल के साथ रक्षा सहयोग के लिए तैयार

हमारा समाज (11 मार्च) के अनुसार इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हरजोग ने 14 वर्ष के बाद तुर्की का दौरा किया है जहां उनका स्वागत तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने किया। दोनों देशों के राष्ट्रपतियों ने घोषणा की है कि इजरायल के राष्ट्रपति का यह दौरा दोनों देशों के संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत करेगा। तुर्की इजरायल के साथ रक्षा एवं उर्जा के क्षेत्र में सहयोग करेगा। 2007 के बाद पहली बार इजरायल के किसी नेता ने तुर्की का दौरा किया है। एर्दोगान ने कहा कि इजरायल के साथ हमारी दोस्ती की महत्त्वपूर्ण शुरुआत हो रहो है। हमारा लक्ष्य इस क्षेत्र में शांति और विकास के नए युग की शुरुआत करना है।

गौरतलब है कि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद इन दोनों देशों के संबंधों क सुधार में तेजी आई है। 2010 में इन दोनों देशों के बीच संबंध तब तनावपूर्ण हो गए थे जब गाजा पट्टी पर इजरायल द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के खिलाफ तुर्की न अपने जलपोतों को फिलिस्तीनियों की सहायता के लिए भेजा था। इजरायली कमांडो ने इन जलपोतों पर हमला किया था, जिसमें कम-से-कम दस तुर्की सैनिक मारे गए थे। 2011 में जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस घटना के बारे में रिपोर्ट जारी की तो तुर्की ने इजरायल के राजदूत को अपने देश से निष्कासित कर दिया था। 2018 में जब अमेरिका ने अपना दूतावास यरुशलम में खोलने की घोषणा की थी तो तुर्की ने इस फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शित करते हुए इजरायल से अपने राजदूत को वापस बुला लिया था। इस पर दोनों देशों के बीच संबंध बेहद तनावपूर्ण हो गए थे और राजनयिक संबंध विच्छेद करने की घोषणा की गई थी। गत वर्ष अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रयासों से तुर्की और इजरायल के बीच संबंधों में सुधार हुआ।

इत्तेमाद (12 मार्च) ने अपने संपादकीय में दोनों देशों के बीच बढ़ते हुए नजदीकी संबंधों की आलोचना की ह। समाचारपत्र ने लिखा है कि मध्य-पूर्व में कई दशकों तक युद्ध और दुश्मनी के बाद इजरायल अरब देशों के साथ अपने संबंधों को पुनर्स्थापित करने का प्रयास कर रहा है और उसे अमेरिका की ओर से हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। सऊदी अरब का नया नेतृत्व अपने

देश की अर्थव्यवस्था को पेट्रोलियम के उत्पादन के व्यापार से हटाकर पर्यटन और व्यापार पर अमल करना चाहता है ताकि पश्चिमी देशों के साथ-साथ यहूदियों के साथ भी संबंधां का लाभ उठाया जा सके। लेकिन अगर यह दोस्ती फिलिस्तीन या ईरान के खिलाफ हो रही है तो विश्व भर के मुसलमानों के लिए यह चिंता का कारण है। सारी दुनिया जानती है कि इजरायल की स्थापना अरब जगत में किसके इशारे पर हुई थी। पश्चिमी देशों के समर्थन के कारण इजरायल दिन-प्रतिदिन ताकतवर बन रहा है। जबकि दूसरी ओर मुस्लिम देश एक दूसरे की कब्र खोदने में लगे हुए हैं। मुस्लिम देशों को चाहिए कि वे इजरायल पर दबाव डालें ताकि फिलिस्तीनियों को उनका उचित अधिकार मिल सके। हालांकि पुराना इतिहास इस बात का साक्षी है कि यहूदियों ने हमेशा मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंपा है और उन्हें धोखा दिया है। इसलिए मुस्लिम देशों को इजरायल के झांसे में आने से बचना चाहिए।

समाचारपत्र ने लिखा है कि 14 वर्ष के बाद अमेरिका के दबाव पर तुर्की और इजरायल के बीच दोस्ती का जो नया दौर शुरू हुआ है उस पर मुस्लिम जगत को नजर रखनी चाहिए। दोनों देशों ने रक्षा और ऊर्जा के क्षेत्र में एक दूसरे से सहयोग करने की घोषणा की है और यह भी कहा गया है कि तुर्की के विदेश मंत्री और ऊर्जा मंत्री शीघ्र ही इजरायल का दौरा करेंगे। इसके बाद समाचारपत्र ने दोनों देशों के बीच रही खटास का भी उल्लेख किया है। समाचारपत्र ने कहा है कि तुर्की और इजरायल के बीच व्यापारिक संबंध दिन-प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। इस समय दोनों के बीच आठ अरब डॉलर का व्यापार होता है जिसका चालू वर्ष के दौरान दस अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है।

ईरान ने अपना दूसरा सैन्य उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा

इंकलाब (11 मार्च) के अनुसार ईरान ने यह घोषणा की है कि उसने एक दूसरा सैन्य उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेज दिया है। यह उपग्रह पृथ्वी से 500 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में चक्कर काट रहा है। इससे पूर्व ईरान ने अपना पहला सैनिक उपग्रह 'नूर' अप्रैल 2020 में अंतरिक्ष में भेजा था जो कि अंतरिक्ष में अभी चक्कर काट रहा है। ईरानी रक्षा मंत्रालय ने यह दावा किया है कि यह ईरानी सेना को एक बहुत बड़ी सफलता है। ईरान द्वारा अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने पर पश्चिमी देशों और इजरायल ने चिंता व्यक्त की है। अमेरिका के रक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि ईरान जिस तरह से अपने सैन्य उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेज रहा है और उसके लिए जो बैलिस्टिक तकनीक इस्तेमाल की जा रही ह उसके

आधार पर वह परमाणु अस्त्र-शस्त्रों की तैयारी भी कर सकता है। इससे विश्व में शक्ति का संतुलन बिगड़ सकता है। अमेरिका के इस दावे का ईरान ने खंडन किया है और कहा है कि वह इस कार्यक्रम के परदे में किसी तरह का बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र या परमाणु अस्त्र-शस्त्र तैयार नहीं कर रहा है।

ईरानी संवाद समिति 'तसनीम' के अनुसार ईरान ने जो नया उपग्रह छोड़ा है उसका नाम 'नूर-2' है। उसे कासेद नामक अंतरिक्ष रॉकेट द्वारा शाहरौद अंतरिक्ष केंद्र से अंतरिक्ष में भेजा गया है। इसमें तरल और ठोस दोनों तरह का इंधन इस्तेमाल किया गया है। गौरतलब है कि हाल ही में ईरान द्वारा उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने के कुछ प्रयास विफल भी रहे थे।

अन्य

दिल्ली के इमामों को 11 महीने के वेतन का भुगतान

इंकलाब (13 मार्च) के अनुसार दिल्ली वक्फ बोर्ड ने यह घोषणा की है कि राजधानी की 4000 पंजीकृत मस्जिदों के इमामों और मुअज्जिनों को उनके सभी बकाया वेतन अदा कर दिए गए हैं और यह धनराशि उनके खातों में पहुंच गई है। गौरतलब है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड प्रत्येक इमाम को 10,000 और मुअज्जिन को 7,000 रुपये का प्रतिमाह भुगतान करता है। वक्फ बोर्ड के अधिकारी महफूज मोहम्मद ने संवाददाताओं को बताया कि क्योंकि दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग से अनुदान पाप्त नहीं हुई थी इसलिए अभी तक उनके वेतन का भुगतान नहीं किया जा सका था। गौरतलब है कि गत एक महीने से इमाम और मुअज्जिन वेतन का भुगतान न किए जाने के कारण वक्फ बोर्ड के बाहर धरना दे रहे थे।

मुगल बादशाह शाहजहां के उर्स में सतरंगी चादर पेश

इंकलाब (2 मार्च) के अनुसार मुगल बादशाह शाहजहां का उर्स ताजमहल में मनाया गया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं द्वारा 1381 मीटर लंबी सतरंगी चादर को मजार पर पेश किया गया। गौरतलब है कि शाहजहां का यह 367वां उर्स था जो कि तीन दिन तक मनाया गया। शाहजहां की

मजार पर चढ़ाई जाने वाली चादर हनुमान मंदिर की ओर स भेजी गई थी। इस रस्म की शुरुआत 25 वर्ष पूर्व हुई थी। इसे हिंदुस्तानी सतरंगी चादर का नाम दिया गया है। इस चादर को तैयार करने का काम एक महीने पूर्व ही शुरू हो जाता है। इसे विभिन्न रंगों में रंगा जाता है और इस पर सितारे लगाए जाते हैं।

करोड़ों रुपये की संपत्ति वक्फ बोर्ड को वापस करने का निर्देश

रोजनामा सहारा (5 मार्च) के अनुसार पटना के जिलाधिकारी ने हसन इमाम वक्फ इस्टेट को यह निर्देश दिया है कि वह वक्फ संपत्ति को एक महीने के भीतर-भीतर खाली करके शिया वक्फ के हवाले करे। इस संपत्ति का मूल्य करोड़ों रुपये बताया जाता है। समाचारपत्र के अनुसार हसन इमाम वक्फ ने आठ संपत्तियां अवैध रूप से बेच दी थी। जब इस पर शिया वक्फ बोर्ड ने शिकायत की तो इस घोटाले की जांच करवाई गई। जिलाधिकारी ने इन वक्फ संपत्तियों के खरीदारों को यह निर्देश दिया है कि वे तत्काल इन संपत्तियों को खाली करके बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड के हवाले कर दें। शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अफजल अब्बास ने कहा है कि ये वक्फ संपत्तियां माफिया गिरोहों ने अवैध रूप से बेची थीं जिसके खिलाफ प्रशासन से शिकायत की गई थी। इस शिकायत की जांच के बाद प्रशासन ने इसे वक्फ बोर्ड को लौटाने का निर्देश दिया है।

नेपाल की राष्ट्रीय सभा में मुस्लिम सदस्य का मनोनयन

इंकलाब (7 मार्च) के अनुसार नेपाल जमीयत उलेमा के अध्यक्ष मुफ्ती मोहम्मद खालिद सिद्दीकी ने 'सिंह दरबार' में आयोजित एक समारोह में अपने पद की शपथ ली। बाद में उनका स्वागत जमीयत उलेमा नेपाल के कार्यालय में किया गया। इस अवसर पर खालिद ने कहा कि पहले मैं

कांग्रेस में था, मगर बाद में मैं पीपुल्स सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हो गया। इस पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने मुझे राष्ट्रीय सभा में मनोनीत किया है। यह पहला अवसर है जब किसी मुसलमान को नेपाल की राष्ट्रीय सभा का सदस्य मनोनीत किया गया हो।

श्रीनगर की जामा मस्जिद में 30 सप्ताह के बाद जुमे की नमाज

सालार (5 मार्च) के अनुसार जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में स्थित प्राचीन जामा मस्जिद में 30 सप्ताह के बाद हजारों लोगों ने जुमे की नमाज अदा की। इससे पूर्व कश्मीर के पुलिस महानिदेशक जामा मस्जिद के क्षेत्र का दौरा करके वहां पर नमाज क प्रबंधों की जांच पड़ताल की। हाजी गुलाम मोहम्मद ने कहा कि मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि इस ऐतिहासिक जामा मस्जिद में नमाज का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। अंजुमन वक्फ के एक पदाधिकारी के अनुसार मीरवाइज उमर फारूक की नजरबंदी के कारण जुमा का

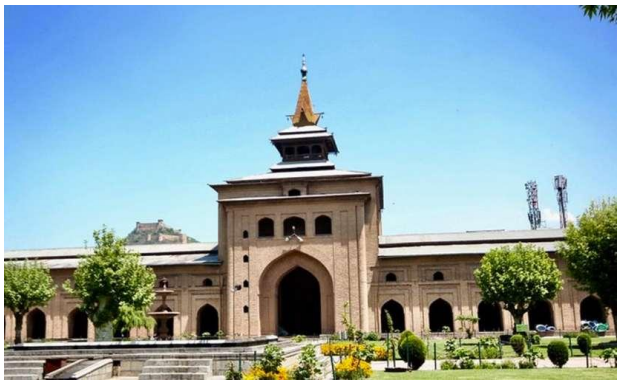

खुत्बा सैयद अहमद नक्शबंदी ने दिया। इस अवसर पर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए थे ताकि कोई अप्रिय घटना न हो।

RNI No. DELHIN/2017/72722

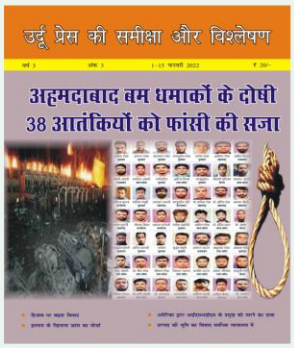

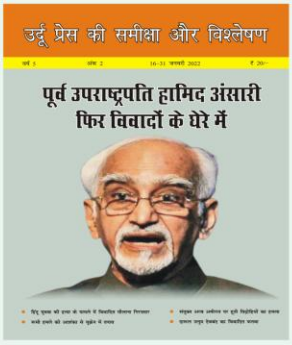

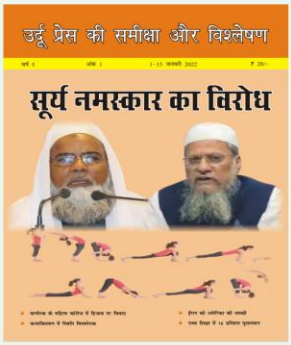

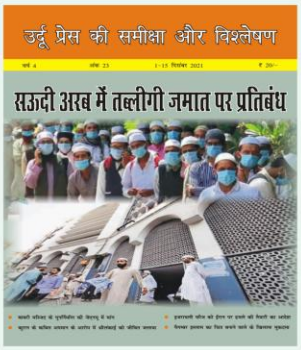

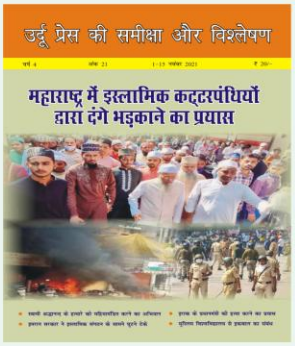

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
॥ प्रदीपयेम जगत् सर्वम् ॥
डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018 • फैक्स : 011-46089365
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in